



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 423]	नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 16, 2018/कार्तिक 25, 1940
No. 423]	NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 16, 2018/KARTIKA 25, 1940

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिसूचना

मुम्बई, 16 नवम्बर, 2018

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

[सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (छठा संशोधन) विनियम, 2018

सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/47.—बोर्ड, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) की धारा 31 के साथ पठित भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 11, धारा 11क की उप-धारा (2) तथा धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2015 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्, -

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (छठा संशोधन) विनियम, 2018 कहा जा सकेगा।
2. ये विनियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त (लागू) होंगे।
3. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2015 में, -

(i) विनियम 2 में, उप-विनियम (1) में, खंड (झ) के पश्चात् और खंड (ज) से पूर्व, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

“(झक) “भगोड़ा आर्थिक अपराधी” से वह व्यक्ति अभिप्रेत होगा, जिसे भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 (द फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेन्डर्स एक्ट, 2018) [2018 का 17] की धारा 12 के तहत भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया गया हो।”

- (ii) विनियम 31 में, उप-विनियम (3) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:
- “(4) संप्रवर्तक (प्रमोटर) और संप्रवर्तक समूह (प्रमोटर ग्रुप) के तहत आने वाली सभी एंटिटियों के प्रकटीकरण (डिस्कलोजर), बोर्ड द्वारा निर्धारित किए गए फॉर्मों के अनुसार, राष्ट्रव्यापी व्यापारिक (ट्रेडिंग) टर्मिनल वाले उन सभी स्टॉक एक्सचेंजों के वेबसाइट पर दिए जाने वाले शेयरधारिता स्वरूप (शेयरहोल्डिंग पैटर्न) में अलग से किए जाएंगे जहाँ एंटिटी की निर्धारित (विनिर्दिष्ट) प्रतिभूतियाँ (सिक्यूरिटीज़) सूचीबद्ध (लिस्टिड) हों।”
- (iii) मौजूदा विनियम 31क निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्,—
- “विनियम 31क. संप्रवर्तक (प्रमोटर) / जनता (पब्लिक) के रूप में किसी व्यक्ति के पुनःवर्गीकरण हेतु शर्तें
- (1) इस विनियम के प्रयोजनार्थ:
- (क) “पुनःवर्गीकरण चाहने वाले संप्रवर्तक (संप्रवर्तकों)” से संप्रवर्तक समूह से संबंधित ऐसे सभी संप्रवर्तक / व्यक्ति अभिप्रेत होंगे, जो जनता (पब्लिक) के रूप में पुनःवर्गीकृत होना चाहते हैं।
- (ख) “पुनःवर्गीकरण चाहने वाले संप्रवर्तक (संप्रवर्तकों) से संबंधित व्यक्तियों” से पुनःवर्गीकरण चाहने वाले उस संप्रवर्तक (उन संप्रवर्तकों) के संबंध में ऐसे व्यक्ति अभिप्रेत होंगे, जो भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2018 [सेबी (इश्यू ऑफ कैपिटल एंड डिस्कलोजर रिक्वायरमेंट्स) रेग्यूलेशन, 2018] के विनियम 2 के उप-विनियम (1) के खंड (तत) के उप-खंड (ii), (iii) एवं (iv) के तहत आते हों।
- (2) संप्रवर्तक या जनता (पब्लिक) के रूप में किसी व्यक्ति के पुनःवर्गीकरण की अनुमति स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटिटी से आवेदन और आवेदन के साथ-साथ सभी संबंधित दस्तावेज प्राप्त होने के बाद ही दी जाएगी, बशर्ते कि इन विनियमों में निर्धारित शर्तों का पालन किया जाए:
- परंतु यह कि एक से अधिक स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटिटियों के मामले में, संबंधित स्टॉक एक्सचेंज आवेदन के संबंध में संयुक्त रूप से निर्णय लेंगे (विनिश्चय करेंगे)।
- (3) संप्रवर्तक समूह से संबंधित संप्रवर्तक / व्यक्ति के जनता (पब्लिक) के रूप में पुनःवर्गीकरण की अनुमति स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा निम्नलिखित शर्तें पूरी किए जाने के बाद ही दी जाएगी:
- (क) सूचीबद्ध एंटिटी द्वारा स्टॉक एक्सचेंजों को पुनःवर्गीकरण के लिए आवेदन निम्नलिखित प्रक्रियाओं को अपनाने के बाद ही किया गया हो और साधारण बैठक में शेयरधारकों की मंजूरी (के अनुमोदन) की तारीख से तीस दिनों के भीतर किया गया हो:
- (i) वर्गीकरण चाहने वाला (वाले) संप्रवर्तक सूचीबद्ध एंटिटी को पुनःवर्गीकरण के लिए निवेदन करेगा (करेंगे) जिसमें शामिल होंगे - ऐसा पुनःवर्गीकरण चाहने का तर्काधार और नीचे खंड (ख) में निर्धारित शर्तों को कैसे पूरा किया जाता है;
- (ii) सूचीबद्ध एंटिटी का निदेशक मंडल (निदेशक बोर्ड) निवेदन का विश्लेषण करेगा और उसे साधारण बैठक में शेयरधारकों के समक्ष मंजूरी (अनुमोदन) के लिए रखेगा और जिसके साथ निवेदन के संबंध में निदेशक मंडल के विचार भी रखे जाएंगे:
- परंतु यह कि पुनःवर्गीकरण चाहने वाले संप्रवर्तक (संप्रवर्तकों) के निवेदन पर विचार करने के संबंध में बोर्ड की बैठक और शेयरधारकों की बैठक की तारीख के बीच कम से कम तीन महीनों का अंतराल होगा, किंतु जो छह महीनों से अधिक का नहीं होगा।
- (iii) पुनःवर्गीकरण चाहने वाले संप्रवर्तक (संप्रवर्तकों) के निवेदन को उस साधारण बैठक में साधारण संकल्प के माध्यम से मंजूरी दी जाएगी, जिसमें पुनःवर्गीकरण चाहने वाला (वाले) संप्रवर्तक तथा पुनःवर्गीकरण चाहने वाले संप्रवर्तक (संप्रवर्तकों) से संबंधित व्यक्ति पुनःवर्गीकरण के ऐसे निवेदन को मंजूर करने के संबंध में मतदान नहीं करेंगे।
- (ख) पुनःवर्गीकरण चाहने वाला (वाले) संप्रवर्तक तथा पुनःवर्गीकरण चाहने वाले संप्रवर्तक (संप्रवर्तकों) से संबंधित व्यक्ति:
- (i) मिलकर, सूचीबद्ध एंटिटी में कुल मताधिकारों का दस प्रतिशत से अधिक धारण नहीं करेंगे;
- (ii) सूचीबद्ध एंटिटी के कामकाज पर, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, नियंत्रण नहीं रखेंगे;

- (iii) (व्यक्तियों) के पास औपचारिक या अनौपचारिक व्यवस्थाओं (इंतजामों / अरेंजमेंट्स) [जिनमें कोई शेयरधारक करार (एग्रीमेंट) भी शामिल हैं] के माध्यम से सूचीबद्ध एंटीटी की बाबत कोई विशेष अधिकार नहीं होंगे;
- (iv) (व्यक्तियों) का सूचीबद्ध एंटीटी के निदेशक मंडल में प्रतिनिधित्व नहीं होगा [उनका नामिती (नामनिर्देशिती / नॉमिनी) निदेशक भी नहीं होगा];
- (v) सूचीबद्ध एंटीटी में प्रबंध-मंडल के मुख्य व्यक्ति (की मैनेजिरियल पर्सन) के रूप में कार्य नहीं करेंगे;
- (vi) भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार 'इरादतन चूककर्ता' (विलफुल डिफॉल्टर) नहीं होंगे;
- (vii) भगोड़े आर्थिक अपराधी नहीं होंगे।
- (ग) सूचीबद्ध एंटीटी:
- (i) न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता संबंधी अपेक्षा का पालन करेगी, जैसा इन विनियमों के विनियम 38 के तहत अपेक्षित है;
- (ii) के शेयरों में व्यापार (ट्रेडिंग) को स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा निलंबित न किया गया हो;
- (iii) की ओर से बोर्ड, स्टॉक एक्सचेंजों या निक्षेपागारों (डिपॉज़िटरीज़) के प्रति कोई देनदारी बकाया न हो।
- (4) पुनःवर्गीकरण चाहने वाला (वाले) संप्रवर्तक, जनता (पब्लिक) के रूप में पुनःवर्गीकरण हो जाने के बाद, निम्नलिखित शर्तों का पालन करेगा (करेंगे):
- (क) उसे (उन्हें) ऐसे पुनःवर्गीकरण की तारीख से सदैव ऊपर उप-विनियम 3 के खंड (ख) के उप-खंड (i), (ii) एवं (iii) में उल्लिखित शर्तों का लगातार पालन करते रहना होगा और ऐसा करने में असफल रहने पर वह (वे) अपने आप ही संप्रवर्तक समूह से संबंधित संप्रवर्तक / व्यक्तियों के रूप में, जो लागू हो, पुनःवर्गीकृत हो जाएगा (जाएंगे);
- (ख) उसे (उन्हें) ऐसे पुनःवर्गीकरण की तारीख से कम से कम तीन वर्षों की अवधि तक उप-विनियम 3 के खंड (ख) के उप-खंड (iv) एवं (v) में उल्लिखित शर्तों का पालन करना होगा और ऐसा करने में असफल रहने पर वह (वे) अपने आप ही संप्रवर्तक समूह से संबंधित संप्रवर्तक / व्यक्तियों के रूप में, जो लागू हो, पुनःवर्गीकृत हो जाएगा (जाएंगे)।
- (5) यदि कोई सार्वजनिक शेयरधारक (पब्लिक शेयरहोल्डर) स्वयं को संप्रवर्तक के रूप में पुनःवर्गीकृत करना चाहता हो, तो उससे यह अपेक्षित होगा कि वह भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 2011 [सेबी (सब्सटैंशियल एक्विज़िशन ऑफ शेयर्स एंड टेकओवर्स) रेग्यूलेशन, 2011] के प्रावधानों (उपबंधों) के अनुसार खुला प्रस्ताव (ओपन ऑफर) लाए।
- (6) संप्रवर्तक समूह से संबंधित संप्रवर्तक / व्यक्ति द्वारा धारित शेयरों को पारेषण (ट्रांसमिशन), उत्तराधिकार, विरासत और उपहार के जरिए दिए जाने की दशा में:
- (क) ऐसा होने होने पर तुरंत, ऐसे शेयर प्राप्त करने वाले को संप्रवर्तक समूह से संबंधित संप्रवर्तक / व्यक्ति, जो भी लागू हो, के रूप में वर्गीकृत कर दिया जाएगा।
- (ख) उसके बाद, यदि शेयर प्राप्त करने वाला, जिसे संप्रवर्तक समूह से संबंधित संप्रवर्तक / व्यक्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया हो, जनता (पब्लिक) के रूप में पुनःवर्गीकृत किए जाने का प्रस्ताव करता हो, तो वह ऐसा कर सकेगा, बशर्ते कि ऊपर उप-विनियम (3) में निर्धारित की गई शर्तों का पालन किया जाए।
- (ग) संप्रवर्तक समूह से संबंधित संप्रवर्तक / व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर, ऐसा व्यक्ति अपने-आप ही संप्रवर्तक समूह से संबंधित संप्रवर्तक / व्यक्ति नहीं रहेगा।

(7) किसी सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटीटी को 'बिना संप्रवर्तक वाली सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटीटी' माना जाएगा, यदि पुनःवर्गीकरण की वजह से या किसी अन्य वजह से, उस एंटीटी में कोई संप्रवर्तक न रह जाए।

(8) निम्नलिखित घटनाओं को महत्वपूर्ण घटनाएं समझा जाएगा और जिन्हें सूचीबद्ध एंटीटी द्वारा स्टॉक एक्सचेंजों को, यथासंभव रूप से जल्द से जल्द किंतु घटना के घटित होने से चौबीस घंटों के भीतर, प्रकट (डिस्क्लोज़) करना होगा:

(क) सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटीटी को पुनःवर्गीकरण चाहने वाले संप्रवर्तक (संप्रवर्तकों) से पुनःवर्गीकरण किए जाने संबंधी निवेदन प्राप्त होना;

(ख) बोर्ड की उस बैठक के कार्यवृत्त, जिसमें ऐसे निवेदन पर विचार किया गया हो (जिसमें निवेदन के संबंध में बोर्ड के विचार शामिल हों);

(ग) सूचीबद्ध एंटीटी द्वारा स्टॉक एक्सचेंजों को संप्रवर्तक / जनता (पब्लिक) के रूप में पुनःवर्गीकरण किए जाने संबंधी आवेदन प्रस्तुत करना;

(घ) ऐसे आवेदन के संबंध में स्टॉक एक्सचेंजों का निर्णय, जो सूचीबद्ध एंटीटी को सूचित किया गया हो।

(9) इस विनियम के उप-विनियम 3, उप-विनियम 4 और उप-विनियम 8 के खंड (क) एवं खंड (ख) के प्रावधान (उपबंध) लागू नहीं होंगे, यदि सूचीबद्ध एंटीटी के संप्रवर्तक (संप्रवर्तकों) / संप्रवर्तक समूह का पुनःवर्गीकरण दिवाला संहिता (इन्सॉल्वेन्सी कोड) की धारा 31 के तहत मंजूर की गई समाधान योजना (रेज़ोल्यूशन प्लान) के अनुसार होता हो, बशर्ते कि पुनःवर्गीकरण चाहने वाले ऐसे संप्रवर्तक (संप्रवर्तकों) के हाथों में सूचीबद्ध एंटीटी का नियंत्रण न रहे।"

(iv) मौजूदा विनियम 102, विनियम 102 के उप-विनियम (1) के रूप में पुनःसंख्यांकित हो जाएगा।

(v) विनियम 102 में, उप-विनियम (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-विनियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

"(2) उप-विनियम (1) के तहत छूट (शिथिलता) प्रदान करने की मांग करने के लिए, बोर्ड के पास आवेदन (जिसमें ब्यौरे देने होंगे और साथ ही उन आधारों का भी उल्लेख करना होगा जिनके आधार पर ऐसी छूट प्रदान करने की मांग की गई है) दाखिल किया जाएगा।

(3) उप-विनियम (2) के तहत उल्लिखित आवेदन के साथ एक लाख रुपये की अप्रतिदेय (लौटाई न जाने वाली) फीस लगाई जाएगी, जो बैंक खाते में एनईएफटी / आरटीजीएस / आईएमपीएस के जरिए सीधे जमा करके या भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमत किसी अन्य माध्यम से या बोर्ड के पक्ष में लिखे गए मांग ड्राफ्ट (डिमांड ड्राफ्ट) [जो मुबई में देय हो] के माध्यम से अदा की जाएगी।"

(vi) अनुसूची-V में, खंड ग में, उप-खंड 10 में, मद (ट) के पश्चात्, निम्नलिखित मद अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

"(ठ) महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के संबंध में प्रकटीकरण:

क. वित्तीय वर्ष के दौरान कितनी शिकायतें दाखिल की गईं

ख. वित्तीय वर्ष के दौरान कितनी शिकायतों का निपटारा किया गया

ग. वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक की स्थिति के अनुसार कितनी शिकायतें लंबित रहीं"

(vi) अनुसूची-VII में, खंड (ग) में, उप-खंड (2) में, मद (ख) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगी, अर्थात्:-

"(ख) जहाँ प्रतिभूतियाँ (सिक्यूरिटीज़) एक ही नाम से धारित हों और किसी नामिती (नामनिर्देशिती / नॉमिनी) का भी उल्लेख न हो, वहाँ प्रतिभूतियों के विधिक स्वामित्व की पहचान और उसके दावे के संबंध में, सभी कानूनी वारिसों से, समुचित न्यायिकेतर स्टांप-पत्र (नॉन-जूडिशल स्टांप पेपर) पर शपथ-पत्र (एफिडेविट) देना अपेक्षित होगा:

परंतु यह कि यदि कानूनी वारिस (वारिसों) / दावेदार (दावेदारों) के नाम का उल्लेख उत्तराधिकार संबंधी प्रमाणपत्र या विल के प्रोबेट या विल या प्रशासन-पत्र (लैटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन) में हो, तो ऐसे कानूनी वारिस (वारिसों) / दावेदार (दावेदारों) की ओर से शपथ-पत्र (एफिडेविट) ही पर्याप्त होगा:

परंतु यह और कि:

(i) जिन प्रतिभूतियों का मूल्य, आवेदन करने की तारीख तक की स्थिति के अनुसार, प्रति सूचीबद्ध एंटीटी, केवल दो लाख रुपये तक की सीमा-रेखा (श्रेडहोल्ड लिमिट) तक ही हो उनके लिए, उत्तराधिकार संबंधी

प्रमाणपत्र या विल का प्रोबेट या विल या प्रशासन-पत्र (लैटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन) या न्यायालय की डिक्री, जो भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के अनुसार लागू हो, प्रस्तुत की जा सकेगी:

परंतु यह कि ऐसे दस्तावेजों के अभाव में, निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए जा सकेंगे:

1. ऐसे सभी कानूनी वारिसों से अनापत्ति प्रमाणपत्र, जिन्हें ऐसे पारेषण (ट्रांसमिशन) से आपत्ति न हो या कुटुंब के समझौते के विलेख (फैमिली सैटलमेंट डीड) की प्रति, जो विधिवत रूप से नोटरी करवाई गई हो और जो मृत (दिवंगत) धारक के सभी कानूनी वारिसों द्वारा निष्पादित की गई हो;
2. समुचित न्यायिकेतर स्टॉप-पत्र (नॉन-जूडिशल स्टॉप पेपर) पर तैयार किया गया क्षतिपूर्ति बंधपत्र (इन्डेमनिटी बॉण्ड), जिसके अंतर्गत शेयर अंतरण अभिकर्ता (शेयर ट्रांसफर एजेंट) / सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटीटी की क्षतिपूर्ति करने का उल्लेख हो;
- (ii) जिन प्रतिभूतियों का मूल्य, आवेदन करने की तारीख तक की स्थिति के अनुसार, प्रति सूचीबद्ध एंटीटी, दो लाख रुपये से अधिक हो उनके लिए, उत्तराधिकार संबंधी प्रमाणपत्र या विल का प्रोबेट या विल या प्रशासन-पत्र (लैटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन) या न्यायालय की डिक्री, जो भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के अनुसार लागू हो, प्रस्तुत की जाएगी;
- (iii) हालाँकि, सूचीबद्ध एंटीटी, अपने विवेकाधिकार से, दो लाख रुपये के प्रतिभूतियों के मूल्य की सीमा-रेखा (श्रेष्ठहोल्ड लिमिट) बढ़ा सकेगी।"

अजय त्यागी, अध्यक्ष,

[विज्ञापन-III/4/असाधारण/345/18]

पाद टिप्पण :

1. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2015, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2015-16/013, 2 सितम्बर 2015 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।
2. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2015 तत्पश्चात् :
 - (क) 22 दिसम्बर, 2015 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2015, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी. एन.आर.ओ./जी.एन./2015-16/027, द्वारा
 - (ख) 25 मई, 2016 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2016, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/001, द्वारा
 - (ग) 8 जुलाई, 2016 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2016, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/008, द्वारा
 - (घ) 4 जनवरी, 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (तीसरा संशोधन) विनियम, 2016, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/025, द्वारा
 - (ङ) 15 फरवरी, 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2017, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी./एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/29, द्वारा

- (च) 6 मार्च, 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (फीस का भुगतान और भुगतान का माध्यम) (संशोधन) विनियम, 2017, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/037 [तारीख 29 मार्च, 2017 को अधिसूचित भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (फीस का भुगतान और भुगतान का माध्यम) (संशोधन) विनियम, 2017, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/038 के साथ पठित], द्वारा
- (छ) 9 मई, 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2018, अधिसूचना सं. एसईबीआई/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2018/10, द्वारा
- (ज) 30 मई, 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2018, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/13, द्वारा
- (झ) 1 जून, 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (तीसरा संशोधन) विनियम, 2018, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/21, द्वारा
- (ञ) 8 जून, 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (चौथा संशोधन) विनियम, 2018, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/24, द्वारा
- (ट) 6 सितम्बर, 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (पाँचवा संशोधन) विनियम, 2018, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/30, द्वारा संशोधित हुए थे।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 16th of November, 2018

Securities and exchange board of india (listing obligations and disclosure requirements) (sixth amendment)

Regulations, 2018

No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/47. — In exercise of the powers conferred by section 11, sub-section (2) of section 11A and section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992) read with section 31 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956), the Board hereby makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, namely,—

1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Sixth Amendment) Regulations, 2018.
2. These regulations shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
3. In the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015,—

- (i) in regulation 2, in sub-regulation (1), after clause (i) and before clause (j), the following clause shall be inserted, namely:

- “(ia) “fugitive economic offender” shall mean an individual who is declared a fugitive economic offender under section 12 of the Fugitive Economic Offenders Act, 2018 (17 of 2018).”
- (ii) in regulation 31, after sub-regulation (3), the following shall be inserted, namely:
- “(4) All entities falling under promoter and promoter group shall be disclosed separately in the shareholding pattern appearing on the website of all stock exchanges having nationwide trading terminals where the specified securities of the entity are listed, in accordance with the formats specified by the Board.”
- (iii) the existing regulation 31A shall be substituted with the following, namely.—

“Reg 31A. Conditions for re-classification of any person as promoter / public

(1) For the purpose of this regulation:

- (a) “promoter(s) seeking re-classification” shall mean all such promoters/persons belonging to the promoter group seeking re-classification of status as public.
- (b) “persons related to the promoter(s) seeking re-classification” shall mean such persons with respect to that promoter(s) seeking re-classification who fall under sub-clauses (ii), (iii) and (iv) of clause (pp) of sub-regulation (1) of regulation 2 of Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018.

(2) Re-classification of the status of any person as a promoter or public shall be permitted by the stock exchanges only upon receipt of an application from the listed entity along with all relevant documents subject to compliance with conditions specified in these regulations;

Provided that in case of entities listed on more than one stock exchange, the concerned stock exchanges shall jointly decide on the application.

(3) Re-classification of status of a promoter/ person belonging to promoter group to public shall be permitted by the stock exchanges only upon satisfaction of the following conditions:

- (a) an application for re-classification to the stock exchanges has been made by the listed entity consequent to the following procedures and not later than thirty days from the date of approval by shareholders in general meeting:
- (i) the promoter(s) seeking re-classification shall make a request for re-classification to the listed entity which shall include rationale for seeking such re-classification and how the conditions specified in clause (b) below are satisfied;
- (ii) the board of directors of the listed entity shall analyze the request and place the same before the shareholders in a general meeting for approval along with the views of the board of directors on the request:

Provided that there shall be a time gap of at least three months but not exceeding six months between the date of board meeting and the shareholder’s meeting considering the request of the promoter(s) seeking re-classification.

- (iii) the request of the promoter(s) seeking re-classification shall be approved in the general meeting by an ordinary resolution in which the promoter(s) seeking re-

classification and persons related to the promoter(s) seeking re-classification shall not vote to approve such re-classification request.

(b) the promoter(s) seeking re-classification and persons related to the promoter(s) seeking re-classification shall not:

- (i) together, hold more than ten percent of the total voting rights in the listed entity;
- (ii) exercise control over the affairs of the listed entity directly or indirectly;
- (iii) have any special rights with respect to the listed entity through formal or informal arrangements including through any shareholder agreements;
- (iv) be represented on the board of directors (including not having a nominee director) of the listed entity;
- (v) act as a key managerial person in the listed entity;
- (vi) be a 'wilful defaulter' as per the Reserve Bank of India Guidelines;
- (vii) be a fugitive economic offender.

(c) the listed entity shall:

- (i) be compliant with the requirement for minimum public shareholding as required under regulation 38 of these regulations;
- (ii) not have trading in its shares suspended by the stock exchanges;
- (iii) not have any outstanding dues to the Board, the stock exchanges or the depositories.

(4) The promoter(s) seeking re-classification, subsequent to re-classification as public, shall comply with the following conditions:

- (a) he shall continue to comply with conditions mentioned at sub-clauses (i), (ii) and (iii) of clause (b) of sub-regulation 3 as specified above at all times from the date of such re-classification failing which, he shall automatically be reclassified as promoter/ persons belonging to promoter group, as applicable;
- (b) he shall comply with conditions mentioned at sub-clauses (iv) and (v) of clause (b) of sub-regulation 3 for a period of not less than three years from the date of such re-classification failing which, he shall automatically be reclassified as promoter/ persons belonging to promoter group, as applicable.

(5) If any public shareholder seeks to re-classify itself as promoter, it shall be required to make an open offer in accordance with the provisions of Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011.

(6) In case of transmission, succession, inheritance and gift of shares held by a promoter/ person belonging to the promoter group:

- (a) immediately on such event, the recipient of such shares shall be classified as a promoter/person belonging to the promoter group, as applicable.
 - (b) subsequently, in case the recipient classified as a promoter/person belonging to the promoter group proposes to seek re-classification of status as public, it may do so subject to compliance with conditions specified in sub-regulation (3) above.
 - (c) in case of death of a promoter/person belonging to the promoter group, such person shall automatically cease to be included as a promoter/person belonging to the promoter group.
- (7) A listed entity shall be considered as '*listed entity with no promoters*' if due to re-classification or otherwise, the entity does not have any promoter;
- (8) The following events shall deemed to be material events and shall be disclosed by the listed entity to the stock exchanges as soon as reasonably possible and not later than twenty four hours from the occurrence of the event:
- (a) receipt of request for re-classification by the listed entity from the promoter(s) seeking re-classification;
 - (b) minutes of the board meeting considering such request which would include the views of the board on the request;
 - (c) submission of application for re-classification of status as promoter/public by the listed entity to the stock exchanges;
 - (d) decision of the stock exchanges on such application as communicated to the listed entity;
- (9) The provisions of sub-regulations 3, 4 and clauses (a) and (b) of sub-regulation 8 of this regulation shall not apply, if re-classification of promoter(s)/ promoter group of the listed entity is as per the resolution plan approved under section 31 of the Insolvency Code, subject to the condition that such promoter(s) seeking re-classification shall not remain in control of the listed entity."
- (iv) the existing regulation 102, shall be re-numbered as sub-regulation (1) of regulation 102.
- (v) in regulation 102, after sub-regulation (1), the following sub-regulations shall be inserted, namely;—
- “(2) For seeking relaxation under sub-regulation (1), an application, giving details and the grounds on which such relaxation has been sought, shall be filed with the Board.
- (3) The application referred to under sub-regulation (2) shall be accompanied by a non-refundable fee of rupees one lakh payable by way of direct credit in the bank account through NEFT/ RTGS/ IMPS or any other mode allowed by Reserve Bank of India or by way of a demand draft in favour of the Board payable in Mumbai.”

- (vi) in Schedule V, in clause C, in sub-clause 10, after point (k), the following point shall be inserted, namely;—

“(l) disclosures in relation to the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013:

- a. number of complaints filed during the financial year
- b. number of complaints disposed of during the financial year
- c. number of complaints pending as on end of the financial year”

- (vii) in schedule VII, in clause C, in sub-clause (2), point (b) shall be substituted with the following, namely;—

“(b) where the securities are held in single name without a nominee, an affidavit from all legal heir(s) made on appropriate non judicial stamp paper, to the effect of identification and claim of legal ownership to the securities shall be required;

Provided that in case the legal heir(s)/claimant(s) is named in the succession certificate or probate of will or will or letter of administration, an affidavit from such legal heir(s) / claimant(s) alone would be sufficient.

Provided further that:

- (i) for value of securities, threshold limit of up to rupees two lakh only, per listed entity, as on date of application, a succession certificate or probate of will or will or letter of administration or court decree, as may be applicable in terms of Indian Succession Act, 1925 may be submitted :

Provided that in the absence of such documents, the following documents may be submitted:

1. no objection certificate from all legal heir(s) who do not object to such transmission or copy of family settlement deed duly notarized and executed by all the legal heirs of the deceased holder;

2. an indemnity bond made on appropriate non judicial stamp paper, indemnifying the Share Transfer Agent / listed entity;

- (ii) for value of securities, more than rupees two lakh, per listed entity, as on date of application, a succession certificate or probate of will or will or letter of administration or court decree, as may be applicable in terms of Indian Succession Act, 1925 shall be submitted;

- (iii) the listed entity however, at its discretion, may enhance value of securities, threshold limit, of rupees two lakh.”

AJAY TYAGI, Chairman
[ADVT.-III/4/Exty./345/18]

Footnote:

- (1) The Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 were published in the Gazette of India on 2nd September 2015 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2015-16/013.
- (2) The Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, were subsequently amended on:
- (a) December 22, 2015 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2015 vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2015-16/27.
 - (b) May 25, 2016 by Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2016 vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/ 2016-17/001.
 - (c) July 08, 2016 by Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2016 vide notification no. SEBI/ LAD NRO/GN/ 2016-17/008.
 - (d) January 4, 2017 by Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Third Amendment) Regulations, 2016 vide notification no. SEBI/ LAD-NRO/GN/ 2016-17/025.
 - (e) February 15, 2017 by Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2017 vide notification no. SEBI/LAD/NRO/GN/2016-17/029.
 - (f) March 6, 2017 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees and Mode of Payment) (Amendment) Regulations, 2017 vide Notification No. LAD-NRO/GN/2016- 17/037 read with March 29, 2017 by Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees and Mode of Payment) (Amendment) Regulations, 2017 vide notification no. SEBI/LAD/NRO/GN/2016-17/38.
 - (g) May 9, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2018 vide notification SEBI/LAD-NRO/GN/2018/10.
 - (h) May 30, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2018 vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/ 2018/13.
 - (i) June 01, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Third Amendment) Regulations, 2018 vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/21.
 - (j) June 08, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Fourth Amendment) Regulations, 2018 vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/ 2018/24.
 - (k) September 06, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Fifth Amendment) Regulations, 2018 vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/30.